मूल्य के संबंध में बकाया राशि की प्रतिशतता निम्नानुसार थी:—

चीनी मौसम	निम्न तारीख को	प्रतिशतता
1993-94	30.9.1994	1.12
1994-95	30.9.1995	2.16
1995-96	30.9.1996	6.97

(घ) सरकार ने पहले से ही सृजित 5 लाख टन चीनी के बफर स्टाक को एक वर्ष तक और बनाए रखने तथा एक वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टाक सृजित करने का निर्णय लिया है।

Demand for Secret Ballot for Recognition of Trade Unions

1744. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a demand for introducing secret ballot for recognition of trade unions; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Cretain Central Trade Union Organisations submitted a memorandum to the Prime Minister urging the Government to frame suitable legislation for recognition of trade unions by Secret Ballot. The issue of determination of the representative character of Trade Unions by Secret Ballot has been referred to the Bipartite Committee constituted by the Ministry of Labour and consisting of representatives of employers and workers. Further course of action will depend on the recommendation of the committee.

खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के उपाय

1745. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिजों के निर्यात में समिति वृद्धि के लिये कौन-कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात हेतु खनिजों के खनन कार्य में निवेश करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु कोई समयबद्ध कदम उठाए है अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) खनिज निर्यात संबंधी राशि में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में इसमें 11% की बढ़ोत्तरी हुई। खनिज क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में भी संशोधन किया गया इससे अनेक क्षेत्रों में निवेश करने में सुविधा होगी जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन करने जिससे खनिज क्षेत्र का विकास होगा और निर्यात-अर्जन में वृद्धि होगी।

Waivers of Anti-Dumping Duties

1746. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the All India Flat Tape Manufactures and All India Plastic Woven Sacks Manufacturers have given some representations for redressal of their grievances on waiver of antidumping duty by the European Union;

(b) if so, details- thereof;

(c) whether Government have taken any action the matter;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons thereof?